भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 876

जिसका उत्तर 7फरवरी, 2024 को दिया जाना है ।

18 माघ, 1945 (शक)

स्मार्टफोन के लिए पीएलआई योजना

876. श्री अनुराग शर्माः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री सी.आर. पाटिलः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्मार्टफोन के उत्पादन की वर्तमान वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्मार्टफोन के उत्पादन हेतु पीएलआई योजना की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कार्य-निष्पादन के आधार पर पीएलआई योजना का विस्तार करने अथवा संशोधित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्मार्टफोन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार करने और उसमें वृद्धि करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क):पिछलेकईवर्षोंमें, भारतकेइलेक्ट्रॉनिकीपारिस्थितिकीतंत्रमेंजबरदस्तवृद्धिऔरविस्तार, निवेशऔररोजगारसृजनदेखागयाहै। वैश्विकइलेक्ट्रॉनिकी आपूर्तिश्रृंखलामेंलगभगमहत्वहीनसे, भारतवर्तमानमेंइलेक्ट्रॉनिकी जीवीसीमेंतेजीसेएकमहत्वपूर्णऔरविश्वसनीयप्लेयरबनरहाहै। अधिकांशवैश्विकऔरभारतीयइलेक्ट्रॉनिकी ब्रांडइसक्षेत्रमेंनिवेशकररहेहैं, बढ़रहेहैंऔररोजगारतैयारकररहेहैं। भारतसरकारकालक्ष्यदेशकेइलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माणक्षेत्रकोव्यापकऔरसुदृढ़करकेइलेक्ट्रॉनिकी जीवीसीमेंभारतकीहिस्सेदारीबढ़ानाहै।

स्मार्टफोनतेजीसेविकास, महत्वपूर्णनिवेशऔररोजगारसृजनकाएकबड़ाउदाहरणहैं । मोबाइलफोनकाउत्पादन 2014-15 मेंआईएनआर 18,900करोड़से ~18.5 गुनाबढ़कर 2022-23 मेंआईएनआर 3,50,000 करोड़होगयाहै (उद्योगअनुमान)। इसकेअलावा, मोबाइलफोनकानिर्यात 2014-15 मेंआईएनआर 1,566 करोड़से ~ 57.5 गुनाबढ़कर 2022-23 मेंआईएनआर 90,000 करोड़ (उद्योगअनुमान) होगयाहै।

(ख):बड़ेहिस्सेमेंइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणक्षेत्रमेंस्मार्टफोनसेगमेंटकीसफलतादूरदर्शीप्रोडक्शनलिंक्डइंसेंटिव (पीएलआई)योजनाकेकारणहुईहै। बड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण (एलएसईएम) केलिएपीएलआईयोजना 01.04.2020 कोअधिसूचितकीगईथी।स्मार्टफोन के उत्पादन के लिए योजना का कार्यकाल 5 वर्ष है।

(ग):एलएसईएमकेलिएपीएलआईयोजना
कार्यान्वयनचरणमेंहैऔरइसस्तरपरकिसीविस्तारअथवासंशोधनकीयोजनानहींहैक्योंकिस्कीमकेअंतर्गतनिष्पादन अनुमानितपरिणामोंकेअनुसारहै।

(घ) और (ङ):सुविधारहितआबादीवालेगांवोंकोमोबाइलकवरेजचरणबद्धतरीकेसेसरकारऔरदूरसंचारसेवाप्रदाताओं (टीएसपी) द्वाराप्रदानकीजातीहै। दूरसंचारसेवाप्रदाता (टीएसपी) द्वारादूरसंचारनेटवर्कोंकाविस्तारउनकीतकनीकी-वाणिज्यिकव्यवहार्यतापरआधारितहै। तथापि, देशमेंसुविधारहितदूरस्थगांवोंमेंदूरसंचारकनेक्टिविटीप्रदानकरनेकेउद्देश्यसेसरकारदूरसंचारसेवाप्रदाताओंकोयूएसओएफकेजरिएवित्तीयसहायताउपलब्धकरातीहै।
सरकारकीसार्वभौमिकसेवादायित्वनिधिकेअंतर्गतनिम्नलिखितस्कीमेंचलरहीहैंजोअभिनिर्धारितसुविधारहितगांवों औरस्थानोंमें 4जी मोबाइलसेवाएंप्रदानकरेंगी

i. 354 शामिल नकिएगएगांवोंकीयोजना: इसयोजनाकेतहतजम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंडऔरअन्यप्राथमिकतावालेक्षेत्रोंकेगांवोंकोशामिलकियागयाहै।
ii. पूर्वोत्तरक्षेत्रमेंमोबाइलकनेक्टिविटीकेलिएव्यापकदूरसंचारविकासयोजना (सीटीडीपी) ।
iii. वामपंथीउग्रवाद (एलडब्ल्युई)प्रभावितक्षेत्रोंमेंमोबाइलसेवाएंप्रदानकरनेकीयोजना।
iv. आकांक्षीजिलोंमेंमोबाइलसेवाएंप्रदानकरनेकेलिएयोजनाएं।
v. अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूहमेंमोबाइलसेवाएंप्रदानकरनेकीयोजना।
vi. देशभरमेंसभीचिन्हितकवर न किएगएगांवोंमें 4 जीसेवाएंप्रदान करने के लिए 4जी संतृप्तियोजना ।

****